

राजस्व अपील संख्या 336/2016 मुकनाराम वगैराह बनाम राज्य

न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी : बी.एल. कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व प्रथम अपील संख्या 336/2016

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोंडेंट्स

1. मुकनाराम पुत्र श्री भाखरराम जाति  
विश्वनोई, निवासी बावरला, तहसील  
व जिला जोधपुर

राजस्थान राज्य द्वारा  
तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध  
आदेश क्रमांक प 12(3-)/राज/आवं/1698-1704 दिनांक  
27.03.2003 जो जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित किया जिसके  
द्वारा ग्राम बनाड के भूमि खसरा नम्बर 51 की सम्वत् 2060 से 2063  
की जमाबन्दी पर से खातेदारान का नाम विलोपित किया गया।

उपस्थिति:-

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलान्तस की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पोंडेंट की ओर से उपस्थित।



:: निर्णय ::

दिनांक: 11 जुलाई, 2019

अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्त  
के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह प्रथम राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू  
राजस्व अधिनियम, 1956 जो जिला कलेक्टर जोधपुर आदेश के द्वारा उनके पत्र क्रमांक प  
12(3-)/राज/आवं/ 1698 -1704 दिनांक 27.03.2003 के द्वारा अपने जिले के समस्त  
तहसीलदारान को मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क होने से मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमि का  
हस्तान्तरण अवैध, तत्सम्बन्धी हस्तान्तरणों की प्रविष्टियां विलोपित करने के बारे में जारी  
किया गया, के संदर्भ में ग्राम बनाड के भूमि खसरा नम्बर 51 की सम्वत् 2060 से 2063 की  
जमाबन्दी पर से खातेदारान का नाम विलोपित किया गया, के विरुद्ध पेश की गई है। अपील

*7-11-19*  
डिवीजनल कमिश्नर


**राजस्व अपील संख्या 336/2016 मुकनाराम वगैराह बनाम राज्य**

के संलग्न अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति हेतु धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु म्याद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है।

हमने उपस्थित दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस को सुना गया दौरान सुनवाई अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि ग्राम बनाड के भूमि ख. न. 51 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार गोपालदास पुत्र सदासुख का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में राज0 भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने से बहुत पहले से ही दर्ज खातेदार रहा है जिसके नाम से खतोनी संवत 2011 से खातेदारी दर्ज है। इसके बाद राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया, उस वक्त भी गिरदावरी संवत 2008 से 2013 गोपालदास की काश्त दर्ज की हुई है।

अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार गोपालदास ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के दिनांक 07.05.1991 के उक्त खसरा नम्बर की भूमि को धन्नाराम पुत्र भंवरलाल दर्जी तथा नरेश सोनी पुत्र श्री गंगाधर जी सोनी आदि 11 व्यक्तियों को हस्तांतरण कर दिया, जिनके नाम से नामान्तरकरण दर्ज होकर खातेदारी दर्ज हो गयी। उक्त खरीददारान खातेदारान में से श्रीमती कमला ने अपने हिस्से के अधीन रकबे को आवासीय भूखण्डों में परिवर्तन करवाकर अतिरिक्त कलक्टर (कृषि भूमि अधिनियम) जोधपुर से पट्टा पत्रावली संख्या 380/91 दिनांक 7.08.1991 को प्लॉट संख्या 1 से 10 कुल 10 भूखण्ड रूपांतरित करवाया, जिसमें से भूखण्ड संख्या 3 व 8 को उसने मेहराराम पुत्र नेताराम मुण्डेल जाति जाट निवासी जाजीवाल कलां को दिनांक 20.08.1991 को बेचान कर दिया, इसके बाद उक्त भूखण्ड संख 3 मेहराराम ने जरिये आम मु0 सहीराम पुत्र सुखराम के द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 17.01.2008 को ही अपीलार्थीगण को हस्तान्तरण किया किया, तब से अपीलार्थीगण काबिज है।

अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थीगण आदेश की आड में उपरोक्त वर्णित ख.न. 51 की भूमि को बाले बाले पटवारी हल्का ने दिनांक 29.04.2007 को डोली बनाम मन्दिर श्री द्वारकानाथ जी के नाम की टिप्पणी खतोनी संवत 2060 से 2063 में बिना किसी आधार के भूमि के दर्ज खातेदारान को सुनवाई व सूचना दिये बिना अंकित कर दी

  
राजस्थान विविजनल काबिज  
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 336/2016 मुकनाराम वगैराह बनाम राज्य

गई जबकि उक्त प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व वर्तमान खातेदारान को बिना पूर्व सूचना के तथा किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिया बिना ही अपीलाधीन आदेश की पालना में उनका नाम जमाबन्दी से विलोपित कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से काबिल खारिज के है।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित ख0सं0 51 की भूमि को बाले-बाले पटवारी ने दिनांक 29.4.2007 को डोली बनाम श्री द्वारकाधीश जी के नाम की टिप्पणी खतौनी सम्वत् 2060 से 2063 में बिना किसी आधार के भूमि के दर्ज खातेदारान को सुनवाई व सूचना दिये ही अंकित कर कर दी। इस प्रकार का नोट विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जिला कलक्टर जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2003 एक प्रशासनिक कार्यवाही/निर्देश है जिसके आधार पर किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है तथा इस प्रकार का आदेश एक शून्य आदेश की श्रेणी में आता है जो निरस्तनीय है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है जिनका नाम विलोपित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई व सूचना का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है जिस कारण भी अपीलाधीन आदेश एवं खतौनी पर दर्ज नोट प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से शून्य एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि, भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने से बहुत पहले से उक्त गोपालदास पुत्र सदासुख खातेदार के रूप में काबिज था तथा भूमि मंदिर की खुदकाश्त की नहीं थी, इस प्रकार मन्दिर के नाम दर्ज करने की कार्यवाही विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। बेचानकर्ता गोपालदास पुत्र सदासुख पुष्करणा जागीर समय से तथा राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से खातेदार काश्तकार दर्ज चले आ रहे है जिनके नाम की प्रविष्टि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के परिवर्तन करने का जिला कलक्टर या तहसीलदार या हल्का पटवारी को कोई अधिकार नहीं है। इस कारण अपीलाधीन आदेश एवं कार्यवाही बिना क्षेत्राधिकार की होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 29.9.2016 को खतौनी की नकल की आवश्यकता होने पर नकल प्राप्त की गई तब जानकारी हुई। अपील को प्रस्तुत



4/11/16  
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर  
जोधपुर

**राजस्व अपील संख्या 336/2016 मुकनाराम वगैराह बनाम राज्य**

करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इसी प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि का कृषि भूमि से आवासीय परिवर्तन हो जाने के कारण उसके पटटे जारी हो गये जिसमें से भूखण्ड संख्या 13 को अपीलान्त मुझ घेवरराम ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के खरीद किया गया है और वर्तमान में वह राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। ऐसे में वे व्यथित पक्षकार होने के कारण अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने अन्य में यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं खतौनी संवत 2060 से 2063 में पटवारी हल्का बनाड द्वारा लगाई गई टिप्पणी दिनांक 29.004.2007 को निरस्त व रद्द किया जाकर विलोपित किये जाने का आदेश फरमावे तथा खातेदारान के नाम खातेदारी को बहाल किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रत्युत्तर में रेस्पोंडेंट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा शासन सचिव देवस्थान विभाग, राज0 सरकार के द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.12 (22) देव/ 91 दिनांक 6 मार्च 2003 जिसके अनुसार "उपरोक्त परिस्थितियों में मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क होने के कारण मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमि का हस्तान्तरण अवैध है एवं राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ.21 (97)/राज/1/79 दिनांक 24.04.1982 पूर्व में ही वापस लिया जा चुका है। तथा देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग का पत्रांक प.12 (22)/देव/91 दिनांक 13.04.1993 तथा इसी विभाग के समसंख्यक पत्रांक प.12 (22)/देव/91 दिनांक 24.05.1996 से वापस लिया जा चुका है। अतः तत्संबंधी हस्तान्तरणों की भू अभिलेख में प्रविष्टियां विलोपित कर पूर्ववत प्रविष्टियां अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त निर्देशानुसार संपूर्ण कार्यवाही दिनांक 21.03.2003 तक संपादित कर राज्य सरकार को पालना प्रतिवेदन प्रेषित किया जाये।" के अनुसरण में अपने पत्रांक क्रमांक प.12 (3-)/राज/आवं/1698-1704 दिनांक 27.03.2003 के द्वारा समस्त तहसीलदार को अपने क्षेत्र में इस प्रकार की हुई कार्यवाही को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किये गये थे। ऐसे में अपीलाधीन आदेश मूल रूप से जिला कलेक्टर जोधपुर का न होकर शासन सचिव, देवस्थान विभाग, जयपुर के द्वारा जारी किया हुआ है। ऐसे में राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 में उक्त आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान संभागीय आयुक्त को नहीं हो



*Handwritten signature*  
**डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर  
जोधपुर**

## राजस्व अपील संख्या 336/2016 मुकनाराम वगैराह बनाम राज्य

सकता है, अपीलार्थीगण को शासन सचिव देवस्थान विभाग के आदेश के विरुद्ध सक्षम स्तर पर चाराजोही करनी चाहिये। अतः अपीलार्थीगण की अपील को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर खारिज की जावें।

हमने उपस्थित दोनों पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में उल्लेखित किये गये देवस्थान विभाग, राज0 जयपुर के पत्र दिनांक 06.03.2003 का जो हवाला दिया गया है, के क्रम में अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने से पूर्व न्यायालय हाजा की उक्त अपील पर सुनवाई क्षेत्राधिकारिता के बिन्दू को निर्णित किया आवश्यक होगा। अपीलान्त के द्वारा जिस अपीलाधीन आदेश की अपील की गई है, वो राज्य सरकार के देवस्थान विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 6.3.2003 की पालना निष्पादन हेतु जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा सम्बन्धित तहसीलदारान को प्रशासनिक निर्देश जारी किये गये हैं, न की न्यायिक आदेश पारित किये जाने जैसी कोई कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के शासन सचिव की ओर से जारी निर्देश/आदेश की अपीलों पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को राज0 भू राजस्व अधिनियम में नहीं दिया गया है। इन सभी तथ्यों/दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात हम इस निश्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थीगण की अपील को क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर खारिज किया जाना उचित होगा। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थीगण अस्वीकार योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(बी. एल. कोठारी)  
डिवीजनल कमिश्नर,  
जोधपुर